थोक में आलू गिरा 3 रु. किलो तक

किसान कम कीमत पर भी कर रहे बिक्री, बारिश से गीला आलू खराब होने की आशंका

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 24 मार्च

भारी आवक के चलते इस महीने अब तक आलू की कीमतें 25 फीसदी तक घटी हैं। किसान उपज खराब होने की चिंता से किसी भी कीमत पर मंडियों में अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू 3.75 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी बाजार में आलू के दाम गिरकर 2.40 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं, जबकि देश में इस कृषि जिंस की उत्पादन लागत 4.5 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। हालांकि आलू की भारी खपत वाले शहरों मुंबई और दिल्ली के आसपास की मंडियों में आलू 5.80 रुपये से 7.00 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है।

देर से बोई गई आलू की फसल पकी हुई थी और यह खुदाई के लिए तैयार थी। लेकिन इस महीने की शुरुआत में यह बेमौसम बारिश से भीग गई। खेतों में कीचड़ होने की वजह से इस पकी हुई फसल को देरी से खोदा गया। इस वजह से आलू में बहुत ज्यादा नमी है।

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के निदेशक आर पी गुप्ता ने कहा, 'आमतौर पर आलू को कमजोर आवक के सीजन में बेचने के लिए गोदामों में भंडारित किया जाता है। लेकिन इस समय मंडियों में आ रहा आलू भंडारण योग्य नहीं है, इसलिए किसान किसी भी कीमत पर इसे बेच रहे हैं। इस बात के पहले ही आसार थे कि अगर फसल कटाई सीजन के दौरान बेमौसम बारिश हुई तो कीमतों में गिरावट आएगी।'

पश्चिम बंगाल के बर्दवान में आलू की अनुमानित आवक सोमवार को 2,205 टन रही, जो इस महीने की शुरुआत में महज 186 टन थी। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई उत्तर प्रदेश से एक पखवाड़े बाद शुरू होती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश भी देश में आलू का एक बड़ा उत्पादक राज्य है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस महीने में अब तक आलू की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि वहां खुदाई में तेजी से इसके दाम बहुत नीचे आ गए थे।

गुप्ता ने कहा, 'बेमौसम बारिश शुरू होने से पहले करीब 80 फीसदी आलू की खुदाई हो चुकी थी। भंडारण कंपनियां और गोदाम मालिक कमजोर आवक के सीजन में बिक्री के लिए आवश्यक मात्रा का भंडारण कर चुके हैं। इसलिए ऑफ सीजन में आलू की उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक गीले आलू की आवक खत्म नहीं हो जाती, तब तक कम से कम दो-चार सप्ताह कीमतें कमजोर बनी रहेंगी।'

वहीं वाशी मंडी के एक कारोबारी और अशोक कुमार हंसमुखलाल ऐंड कंपनी में साझेदार हंसमुखभाई ने कहा, 'मार्च में करीब 20 फीसदी फसल बाजार में आई है, इसलिए चालू सीजन में कुछ भी असामान्य नहीं है। केवल आलू की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए किसान मंडियों मे भारी मात्रा में आलू की बिक्री कर रहे हैं।' हालांकि विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि मार्च में बारिश से फसल को मामूली नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में कहा है कि इस साल भारत में 4.27 करोड़ टन आलू उत्पादित होगा, जो पिछले साल 4.15 करोड़ टन था। एक आलू अनुसंधान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह सही है कि किसान गोदामों में आलू भंडारण की लागत का बोझ वहन नहीं कर सकते। इसलिए वे सीधे मंडियों में बिक्री कर रहे हैं। लेकिन इस साल ज्यादा उत्पादन होने से आलू का भंडारण नहीं होगा।'

प्रमुख मंडियों में आलू की मॉडल कीमत

मंडी	2 मार्च 2015	23 मार्च 2015	बदलाव (फीसदी)
राजकोट	5.00	3.75	-25.00
बर्दवान	5.20	4.00	-23.07
इंदौर	6.25	5.00	-20.00
मुंबई	8.50	7.00	-17.64
आजादपुर	6.70	5.80	-13.43
आगरा	5.80	6.00	3.44
फर्रुखाबाद	2.80	3.00	7.14

स्रोत : एगमार्केट डॉट एनआईसी डॉट इन
मुंबई कीमतों के लिए वाशी मंडी
(कीमतें रुपये प्रति किलोग्राम)

कंपोजिशन शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ ज्वैलर

बीएस संवाददाता
जयपुर, 24 मार्च

राजस्थान सरकार द्वारा जवाहरात और सराफा कारोबार पर कंपोजिशन शुल्क लगाने का ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर, सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर, डायमंड एसोसिएशन, राजस्थान सराफा संघ और सीतापुरा जेम्स ऐंड ज्वैलरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जयपुर ने संयुक्त रूप से विरोध करने का निर्णय लिया है। ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष विजय केडिया ने कहा, 'सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में वैट 2003 की धारा 5(1) के तहत कंपोजिशन राशि 0.25 फीसदी से बढ़ाकर 0.75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। यह 300 फीसदी की अप्रत्याशित बढ़ोतरी है, जिसका पूरे आभूषण कारोबार पर पर बुरा असर पड़ेगा।'

इन संगठनों के अधिकारियों ने कहा कि एक ओर तो सरकार 'मेक इन इंडिया' और 'मेक इन राजस्थान' का विजन रखती है और स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं दूसरी ओर सरकार के स्तर से ही उद्योग व व्यापार विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं। जयपुर के आभूषण विनिर्माताओं ने विश्व स्तर पर देश को नई पहचान दिलाई है। अकेले सीतापुरा क्षेत्र में करीब 125 से ज्यादा ज्वैलरी इकाइयां हैं। राज्य में सराफा कारोबार से करीब 5 लाख व्यापारी और लाखों कारीगर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कंपोजिशन शुल्क में भारी बढ़ोतरी से जवाहरात एवं सराफा उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

कम उत्पादन का दलहन कीमतों पर असर

सुशील मिश्र
मुंबई, 24 मार्च

मौसम की मार से दलहन उत्पादन घटने की आशंका है, लेकिन दलहन कारोबारियों की भारतीय दाल बाजार को संगठित करने और उसका वायदा कारोबार शुरू करने की कोशिशों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दलहन एवं अनाज व्यापार के प्रमुख संगठन इंडिया पल्सेस ऐंड ग्रेन्स एसोसिएशन (आईपीजीए) ने चने की तरह अन्य दलहनों का भी वायदा कारोबार शुरू करने की मांग दोहराई है। हालांकि उत्पादन कम होने की वजह से फिलहाल यह मुश्किल है और इससे दलहन कीमतों में बढ़ोतरी के आसार हैं।

आईपीजीए के अनुसार अंतरराष्ट्रीय दलहन सम्मेलन 2016 का तीसरा संस्करण जयपुर में फरवरी 2016 में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में दुनियाभर के दलहन कारोबारी संगठन, किसान और व्यापारी शामिल होंगे। आईपीजीए के चेयरमैन प्रवीण डोंगरे का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है। विश्व स्तर पर सभी सहभागी देशों द्वारा दलहन के प्रति उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, खाद्यान्न उद्योग में दालों के उपयोग में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कारोबार में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में चने की तरह दूसरी दलहन फसलों का वायदा कारोबार शुरू होना दलहन उद्योग के विकास के लिए बेहतर होगा। आईपीजीए सरकार के सामने अपनी मांग और प्रस्ताव कई बार रख चुकी है। दलहन कारोबारियों की इस मांग पर वायदा बाजार आयोग के चेयरमैन रमेश अभिषेक ने कहा कि जिंस बाजार के नियामक के तौर पर हमारी कोशिश रहती है कि बाजार के सभी भागीदारों को फायदा हो और कारोबार पारदर्शिता के साथ हो, ताकि वायदा बाजार के साथ-साथ हाजिर बाजार का भी विकास हो सके। हम जिंसों में ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के साथ वायदा बाजार को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। लोगों में और जागरूकता लाने की जरूरत है। जहां तक दलहन के वायदा बाजार की बात है, हमें इस क्षेत्र में अहम सुधार होने की उम्मीद है। फिलहाल एफएमसी जिन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसमें से एक वायदा बाजार में उपलब्ध भंडारण की गुणवत्ता है। कानूनी तौर पर यह अनिवार्य है कि विनिमय क्षेत्र में सभी भंडारों का पंजीकरण भंडार नियामक के पास होना चाहिए। वर्ष 2013 में सभी एक्सचेंजों में सेटलमेंट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, ताकि जिंस बाजार के सभी हितधारकों को वायदा कारोबार में शामिल होने का आत्मविश्वास पैदा किया जा सके।

आईपीजीए के उपाध्यक्ष विमल कोठारी का कहना है कि इस साल कम उत्पादन के चलते आयात पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस सीजन में आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। इस वजह से सरकार का कोई भी नया कदम उठाना मुश्किल है, क्योंकि कृषि जिंसों का कारोबार और इनकी कीमतें बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर दबाव रहता है। इस साल रबी सीजन में चने का उत्पादन करीब 15 फीसदी कम रहने की आशंका है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू फसल वर्ष 2014-15 में देश का दलहन उत्पादन 184.3 लाख टन रहेगा, जो पिछले फसल वर्ष (जुलाई से जून) के दलहन उत्पादन 197.8 लाख टन से 7 फीसदी कम है। इस सीजन में आयात करीब 40 लाख टन रहने का अनुमान है जो पिछले साल की तुलना में करीब 5 लाख टन ज्यादा है।

उत्पादकता में कमी

- इस साल दलहन फसलों को नुकसान की खबरों से उत्पादकता में गिरावट आने के आसार
- कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू फसल वर्ष में 184.3 लाख टन दलहन उत्पादन

ईरान को फिर बासमती चावल का निर्यात

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 24 मार्च

भारत से बासमती चावल का निर्यात एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद बढ़ रही है क्योंकि देश के अधिकारी भारतीय निर्यातकों को परमिट जारी कराने के लिए ईरान को आश्वस्त कराने में सफल रहे हैं। ईरान ने भारत से बासमती चावल के आयात को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया था जिसकी वजह से भारत को अपनी शीर्ष कृषि निर्यात वस्तु के दर्जे को खोना पड़ा था। पिछले कुछ महीने में भारत के अधिकारियों ने ईरान के अधिकारियों से कई दौर की वार्ताएं कीं। इसके बाद ईरान के अधिकारियों ने इच्छुक निर्यातकों के लिए आयात परमिट जारी करने पर सहमति बनाई जिनमें भारत भी शामिल है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय का कहना है, 'भारत अगले साल की शुरुआत से बासमती चावल का निर्यात शुरू हो जाएगा।'

वर्ष 2013-14 में भारत से बासमती चावल निर्यात के निर्यात में 10 फीसदी की कटौती की उम्मीद है क्योंकि ईरान ने ताजा मांग अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। ईरान आमतौर पर विभिन्न देशों के इच्छुक निर्यातकों को आयात परमिट जारी करता है जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन ईरान ने अक्टूबर 2014 के बाद से कोई भी ताजा आयात परमिट जारी नहीं किया है। हालांकि मौजूदा और पिछली मांग की पूर्ति की जा रही है लेकिन नई मांग की प्रक्रिया बंद हो गई है।

अप्रैल से दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान भारत के कुल बासमती चावल निर्यात में 6 फीसदी की कमी आई और यह 25.7 लाख टन हो गया जो इससे पिछले साल की समान अवधि के दौरान 27.4 लाख टन था। कीमतों के लिहाज से भी देखें तो बासमती चावल के निर्यात में 2.64 फीसदी की गिरावट आई है और यह मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीने में 337.32 करोड़ डॉलर हो गया जो पिछले साल की समान अवधि में 346.47 करोड़ डॉलर हो गया। हालांकि इस साल प्रति टन औसत प्राप्ति 80,000 रुपये हो गई जो पिछले साल के दौरान 75,000 रुपये था। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान को किए गए निर्यात में इस साल 15-20 फीसदी की कमी आई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के निदेशक ए के गुप्ता का कहना है, 'बासमती चावल के ईरान में निर्यात को लेकर भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दिक्कत इसी बात की है कि ईरान ने कोई आयात परमिट जारी नहीं किया है जो यह आमतौर पर कोई भी उत्पाद अपने क्षेत्र में लाने से पहले किसी भी देश के साथ करता है। अतिरिक्त आपूर्ति की वजह से अक्टूबर में ईरान ने यह कदम उठाया था। पिछले कुछ सालों के दौरान ईरान ने बड़ी तादाद में भारत से बासमती चावल का आयात किया था।'

ईरान सबसे बड़ा बासमती चावल आयातक है जिसमें भारत से कुल महंगे चावल का निर्यात करीब 60-65 फीसदी तक होता है। वर्ष 2013-14 में भारत ने ईरान को 183.45 करोड़ डॉलर के 14 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया था। वर्ष 2012-13 के दौरान ईरान में कुल 10 लाख टन बासमती चावल का निर्या किया गया था जो करीब 118.7 करोड़ डॉलर का था। भैंस के मांस के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि जिंस बासमती चावल ही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक ईरान के चावल का उत्पादन वर्ष 2014 में रिकॉर्ड स्तर पर 30 लाख टन रहा जो इससे पिछले सालों में तकरीबन 29 लाख टन और 28 लाख टन रहा था। गुप्ता का कहना है कि एक बार जब आयात परमिट जारी कर दिया जाएगा तब भारत ईरान में बासमती चावल का निर्यात शुरू करेगा। बासमती चावल के अलावा भारत गैर-बासमती चावल और दूसरे अनाज का निर्यात भी ईरान को करता है और यह करीब 15 करोड़ डॉलर सालाना है।

Indo Count Industries Ltd

Regd. Office : Office No. 1, Plot No. 266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, Dist. Kolhapur 416 109 Website: www.indocount.com CIN -L72200PN1988PLC068972

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported lost/misplaced and the registered holders therefor/ claimants thereto have requested the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificates(s):

SR. No	FOLIO No.	NAME	NO. OF SHARES	DISTINCTIVE NO	SHARE CERTIFICATE NO.	CITY
01	080578	Subhash S. Moley Sheetal S. Moley	100	1269371-1269470	12701	Mumbai
02	080230	Usha Bajaj	200	7021601-7021800	139343 -129344	Kolkotta
03	087492	Anita Dalmia	100	14735001-14735100	85402	Kolkotta
04	046413	Pawan Khandelwal	110	14596680-14596789	84805 - 84806	New Delhi

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid Share Certificate(s) should lodge the claim in writing with Registrar and Share Transfer Agent M.s Link Intime India Pvt. Ltd 44, Community Centre, Phase-I, Near PVR, Naraina Ind. Area, New Delhi-110028 within 15 days from the publication hereof. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share Certificate(s) pursuant to Rule 6 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014.

For Indo Count Industries Ltd.
Sd/-
Company Secretary

Date: 25/03/2015

(This is only an advertisement for Information purposes and not a Prospectus announcement.)

O. P. CHAINS LIMITED

CIN: U27205UP2001PLC026372

Our Company was originally incorporated on December 4, 2001, as "O. P. Chains Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies,Uttar Pradesh, Kanpur. Subsequently, our Company has received a Certificate of Commencement of Business dated December 7, 2002 issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur.For details, please see section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 106 the Prospectus.

Registered Office: 8/16 A, Seth Gali, Agra - 282003, Uttar Pradesh, India; **Tel:**+91- 0562-3059117; **Fax:**+91-0562-4044990;
Email: cs@opchainsltd.com; **Website:** www.opchainsltd.com
Contact Person: Mrs. Swapnla Gupta (Company Secretary & Compliance Officer)

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 18,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF O. P. CHAINS LIMITED ("O. P. CHAINS" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 11.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 1.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 203.50 LAKHS, OF WHICH 1,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 11.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 11.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 17,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 11.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 192.50 LAKHS (HEREINAFTER REFERRED TO AS "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.00 % AND 25.54 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 11.00. THE ISSUE PRICE IS 1.1 TIMES OF THE FACE VALUE

THIS ISSUE IS BEING IN TERMS OF CHAPTER XB OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009 AS AMENDED FROM TIME TO TIME.
THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 43(4) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009
FOR FURTHER DETAILS SEE "ISSUE RELATED INFORMATION"BEGINNING ON PAGE 210 OF THE PROSPECTUS
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 10,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 10,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE
OPENS ON : MONDAY, MARCH 30, 2015
CLOSES ON : WEDNESDAY, APRIL 8, 2015

ASBA* **Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!**
*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details, check section on ASBA below.

PLEASE NOTE THAT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SEBI CIRCULAR BEARING NUMBER CIR/CFD/DIL/1/2011 DATED APRIL 29, 2011, ALL APPLICANTS WHO ARE QIBS, NON – INSTITUTIONAL INVESTORS SHALL MANDATORILY MAKE USE OF ASBA FACILITY. ALL QIBS AND NON-INSTITUTIONAL INVESTORS, COMPLYING WITH THE ELIGIBILITY CONDITIONS OF SEBI CIRCULAR DATED DECEMBER 30, 2009, MUST MANDATORILY INVEST THROUGH THE ASBA PROCESS.
NON-RETAILS INVESTORS HAVING BANK ACCOUNT WITH THE SCSBs THAT ARE PROVIDING ASBA IN CITIES / CENTERS WHERE NON-RETAIL INVESTORS ARE LOCATED ARE MANDATORILY REQUIRED TO MAKE USE OF ASBA FACILITY, OTHERWISE APPLICATIONS OF NON-RETAIL INVESTORS ARE LIABLE FOR REJECTION. ALL NON-RETAIL INVESTORS ARE ENCOURAGED TO MAKE USE OF ASBA FACILITY WHEREVER SUCH FACILITY IS AVAILABLE.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. OM PRAKASH AGARWAL, MR. ASHOK KUMAR GOYAL & MR. SATISH KUMAR GOYAL

Listing: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the BSE SME Platform. In terms of the Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended from time to time, we are not required to obtain an in-principle listing approval for the shares being offered in this issue. However, our Company has received an approval letter dated November 19, 2014 from BSE for using its name in this offer document for listing of our Equity Shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE").

Disclaimer Clause of SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations 2009, the Draft Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 198 of the Prospectus.

Disclaimer Clause of BSE (Designated Stock Exchange):): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has not been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page 204 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects As Per Memorandum of Association of Our Company: 1. To takeover the existing business of M/s O. P. Chains & Others AOP and its all assets and liabilities and other title, rights, goodwill or any other assets or liabilities acquired or self generated. To acquire all its tangible and non tangible assets and liabilities of the above AOP. 2. To carry on the business of manufacture, dealers, exporter, importer of precious and non precious metal in India or Outside India. The precious metal will include gold, silver, platinum or any metal or compound which is termed as precious metal on the international or national recognized metal exchange. The non precious metal includes the iron, cooper, aluminum etc or any metal or compound which is termed as precious metal on the International or national recognized metal exchange. 3. To carry to business of manufacture, dealers, exporter, importer of jewelry, fancy items, daily use items made up of precious and non-precious metal in India or outside India. The precocious metal will include gold, silver platinum or any metal or compound which is termed as precious metal on the International or national recognized metal exchange. The non precious metal includes the Iron, cooper aluminum etc. or any metal or compound which is termed as precious metal on the International or national recognized metal exchange. 4. To open the subsidiary or wholly owned subsidiary in India or outside India to transact the business of manufacture trading importer, exporter of precious metal, non precious metal, items of personal or industrial use made up from the precious metal and non precious metal. 5. To carry on the business of lending money as loan or financial assistance, make investments in securities or projects or business of other nature, accept money from others, to act as merchant bankers, investors, lenders occupiers, installers, to draw, make, accept, endorse, discount, negotiate, execute and issue bills of exchange, promissory notes, and other negotiable instruments, subjects to approval of Reserve Bank of India. 6. To purchase, acquire take on lease or in exchange or in any other lawful manner make investment in Property and to turn the same in to account, develop the same and dispose off or maintain the same and to create Land Banks and to build townships, commercial complex, or other buildings or conveniences thereon and to equip the same or any part there of with all or any amenities or conveniences and to deal with the same in any manner what so ever and to carry on the business as planners, designers, architects, engineers, promoters, consultants, advisors, interior decorators, real estate agents in all the matters connected with real estate and building construction and to promote, manage and administer co-operatives, groups housing societies for buying, maintain and developing lands, building, hereditament, facilities, amenities and to manage sell, allot lease out houses, apartments, flats, shops, offices to the shareholders, members, participants of such co-operatives, groups, societies or to any other person on their behalf and to invest the fund of the Company in Securities, Shares, Government Securities, Commodities and Derivatives from time to time in the ordinary courses of business.

Amount of Share Capital of Our Company And Capital Structure: Authorized Share Capital of ₹ 725 Lacs divided into 72,50,000 equity shares of Face Value of ₹ 10 each; Issued, Subscribed and paid-up Capital Prior to the issue is ₹ 500 Lacs divided into 50,00,000 equity shares of Face Value of ₹ 10. Proposed Post Issue Paid-up Capital: ₹ 685 Lacs divided into 68,50,000 equity shares of ₹ 10 each.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is limited.

Signatories to MoA and AoA:

Original Signatories		Current Promoters	
Name	No. of Shares	Name	No. of Shares
Mr. Om Prakash Agarwal	20,100	Mr. Om Prakash Agarwal	9,08,100
Mr. Ashok Kumar Goyal	20,000	Mr. Ashok Kumar Goyal	8,70,000
Mr. Satish Kumar Goyal	20,000	Mr. Satish Kumar Goyal	8,70,000
Mr. Moon Goyal	1,000		
Mrs. Kusum Agarwal	4,000		
Mr. Kailash Chand	1,000		
Mrs. Heera Devi	1,000		

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Hem Securities

HEM SECURITIES LIMITED
203, Jaipur Tower, M.I. Road, Jaipur -302 001, Rajasthan, India.
Tel No: +91 - 141 - 2378 608 / 2363 278
Fax No: +91 - 141 - 5101 757
Email: ib@hemonline.com;
Website: www.hemonline.com
Investor Grievance Email: redressal@hemonline.com
SEBI Registration No: INM000010981
Contact Person: Ms. Vinita Gupta

REGISTRAR TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
E2 Ansa Industrial Estate, Sakivihar Road, Sakinaka, Andheri East, Mumbai- 400072
Tel: +91 22 40430200
Fax: +91 22 28475207
Email: ashok@bigshareonline.com
Website: www.bigshareonline.com
SEBI Registration No.: INR000001385
Contact Person: Mr. Ashok Shetty

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Mrs. Swapnla Gupta
8/16 A, Seth Gali, Agra – 282003, Uttar Pradesh, India
Tel:+91- 0562-3059117;
Fax:+91- 0562- 4044990;
Email: cs@opchainsltd.com;
Website: www.opchainsltd.com

Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary accounts and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the issue. Full copy of the Prospectus is available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.hemonline.com and website of the company www.opchainsltd.com

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application forms can be obtained from the Issuer Company: **O. P. CHAINS LIMITED**, Lead Manager HEM SECURITIES LIMITED and Collection Centers of the Bankers to the issue: ICICI Bank Limited Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange. The list of SCSBs is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com. Application forms can also be downloaded from the website at www.bseindia.com

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors may apply through the ASBA process. ASBA can be availed by all the investors. Non-Retail investors have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of BSE Limited. ASBA forms can be obtained from the list of banks that is available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 217 of the Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE AND ESCROW COLLECTION BANK / REFUND BANKER: ICICI Bank Limited

Attention Investors

The Reserve Bank of India has issued standard operating procedure in terms of paragraph 2(a) of RBI circular number DPSS.CO.CHD.No./133/04.07.05/2013-14 dated July 16, 2013, detailing the procedure for processing CTS 2010 and Non-CTS 2010 instruments in the three CTS grid locations. As per this circular, processing of non-CTS cheques shall be done only one day of the week. SEBI Circular No. CIR/CFD/DIL/3/2010 dated April 22, 2010 fixes the time between issue closure and listing at 12 days. In order to enable compliance with the above timelines, investors are advised to use CTS cheques or use ASBA facility to make payment. Investors using non CTS cheques are cautioned that applications accompanied by such cheques are liable to be rejected due to any clearing delays beyond 6 working days from the date of the closure of the issue, in terms of the aforesaid SEBI Circular.

For O. P. CHAINS LIMITED
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Mr. Om Prakash Agarwal
Managing Director

Place : Agra
Date : March 24, 2015

O. P. Chains Limited is proposing, subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed to Prospectus with the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur. Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.hemonline.com the website of SME Platform of BSE Limited ("BSE") at www. bseindia.com and website of the company www.opchainsltd.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details Investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" page 12 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Raka